

# PESTICIDES IN MY FOOD? NO, THANK YOU!

An apple a day keeps good health away. Yes, you read right! The government's own reports suggest that **banned pesticides like Chlordane, Heptachlor**

**and DDT, are present in our food.** Chlordane, for instance, is associated with severe damage to the central nervous system and is known to adversely affect liver, lungs, kidney and the eyes! Further, **pesticides not meant for use on particular crops are repeatedly showing up as residues in those very foods.**

**As per law**, monocrotophos, known for its 'acute' (immediate) as well as 'chronic' (long term) adverse health effects, and one of the most-used pesticides in India, is not allowed to be used on vegetables. However, monocrotophos has been repeatedly found in vegetables tested for toxic residues by different agencies in India. **Even the pesticides/toxins allowed in agriculture do end up as residues in our food, and well above the legal permissible limits.** These are just a few examples of how our food, water and soils in India are getting contaminated by chemical pesticides.

Just think of all the effort you put in to ensure that you pick fresh fruits and vegetables from the supermarket shelves or from your local vendor, and diligently wash it, cut it, cook it and feed your loved ones and yourself... only to let the toxic trail of chemicals trickle into your system. Fruits, vegetables, meat, poultry and milk are all laced with high levels of pesticide residue — numerous times, above the maximum residue limits (MRL) set by Indian law. Not just this, our drinking water is also contaminated! Worse, even mother's milk is laden with poison!!

**And no one  
is monitoring or taking any  
deterrent action  
to stop this  
poisoning of the nation!**

LOG ON TO  
[www.indiaforsafefood.in](http://www.indiaforsafefood.in) and sign the petition.

Or just GIVE A MISSED CALL on  
**022 3301 0031**  
and we'll convey your message

## THE GOVERNMENT'S NOT WATCHING

It is evident that the origin of the problem is in our farms. Here, the Indian Government continues to support the use of these deadly chemicals, despite being cognizant of these problems and despite having alternatives to chemical pesticides. This in turn keeps the pesticide industry prosperous and helps them flourish at the cost of the citizens' health. To add insult to injury now the government has begun promoting Genetic Modification of crops (food) as a solution, which is hazardous and worse, irreversible. Instead the government should be providing preferential support to the safer alternatives whereas there is not even a level playing field being created for them at this point of time and our annadataas, the farmers, are left with no choices. Meanwhile they are themselves reeling under a severe crisis due to rising costs of cultivation, indebtedness, health problems due to exposure to pesticides and other related issues.

## YET, THERE IS SOME GOOD NEWS!

The good news is that world-over, there is growing research and experiential evidence about the viability and benefits of safer alternatives for farming. For instance, in Andhra Pradesh, lakhs of farmers have shifted to farming without the use of chemical pesticides, a practice they call "Non Pesticidal Management" (NPM). Reports demonstrate that farmers find this farming more profitable! If there are no pesticides used in food production, there would be no pesticide residues in our food!

Since the Indian Government shows little inclination to wean off the nasties, and prefers to be supportive of the pesticides industry, **we, the consumers have to come together and demand safe food. As citizens, we have a right to safe food.**

## ALL OF US CAN BECOME AGENTS OF CHANGE TO IMPROVE THIS SITUATION!

As citizens who are being subjected to such poisoning, we can demand that the Government put the safety of its people and the environment ahead of the profits of companies producing such dangerous chemicals and that the Government take responsibility and provide us access to safe food.

**We can demand that the Government:**

- **Promote and encourage organic / ecological / natural farming, without pesticides and Genetically Modified Organisms.**
- **Ensure access to organic food (also specifically for pregnant/lactating mothers & children).**
- **Ban pesticides, which have been banned in other countries.**

**We'll take it to the Agriculture Minister for you. The website also has information on what else you can do to get involved and make change happen.**

## मेरे खाने में कीटनाशक?

### जी नहीं, धन्यवाद !

रोज एक सेव का सेवन कर आप अपने स्वास्थ्य को खटाई में डाल सकते हैं। जी हाँ, आपने सही पढ़ा ! सरकार की अपनी रिपोर्ट कहती है कि प्रतिबंधित कीटनाशक जैसे क्लोरडेन, हेप्टाक्लोर और डी डी टी हमारे भोजन में मौजूद हैं।

क्लोरडेन की वजह से हमारे नर्वस सिस्टम को क्षति पहुँचती है। इतना ही नहीं इससे फेफड़ों, गुर्दे, और किडनी के साथ ही आँखों पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। जिन कीटनाशकों का इस्तेमाल किसी फसल के उत्पादन में नहीं होना चाहिए, उनके अंश भी भोजन में मिल रहे हैं।

कानून के अनुसार, मोनोक्रोटोफॉस जिसे उसके तीव्र (एक्यूट) और दीर्घकालीन (क्रोनिक) प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों के लिए जाना जाता है, यह भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों में से एक है। हालाँकि, भारत में कई एजेंसियाँ अपने शोध में सब्जियों में मौजूद जहरीले पदार्थों में मोनोक्रोटोफॉस की उपस्थिति के आंकड़े प्रस्तुत कर चुकी हैं। जिन कीटनाशकों/ जहरीले पदार्थों की खेतों में इस्तेमाल करने की अनुमति है, उनके अंश भी भोजन में कानूनी अनुमति की सीमा से बहुत ज्यादा पाए गये हैं। इसके पर्याप्त उदाहरण हैं कि भारत में किस तरह हमारा भोजन, पानी और मिट्टी रासायनिक कीटनाशकों की वजह से प्रदूषित हो रहे हैं।

आप अपने प्रयासों के बारे में जरा सोचिए जिससे आप यह सुनिश्चित करते हैं कि सुपरमार्केट, स्थानीय बाज़ार या छोटे विक्रेता से खरीदे गये सब्जी या फल ताजे हों, आप उन्हें पानी से धोते हैं, साफ़ करते हैं, काटते हैं, पकाते हैं, और फिर अपने प्रियजनों को खिलते हैं या खुद खाते हैं। आप इतने प्रयास सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनमें मौजूदा जहरीले पदार्थ धीरे धीरे चले जाएँ। परन्तु क्या आप साफ़ सुथरा भोजन कर पाते हैं? वास्तव में फल, सब्जियाँ, मांस, पौल्ट्री और दूध में बहुत ज्यादा मात्रा में कीटनाशक होते हैं। कई मर्तबा तो यह भारतीय कानूनों में तय अधिकतम शेष सीमा (एम आर एल) से बहुत ज्यादा होते हैं। इतना ही नहीं, हमारा पेय जल भी प्रदूषित हो चुका है ! सबसे विषम स्थिति तो यह है कि माँ का दूध भी जहरीला हो चला है !!!

## पूरे देश को जहर देने की प्रक्रिया की निगरानी या इसे रोकने के लिए कठोर करवाई कोई नहीं कर रहा है!

### सरकार अनदेखी कर रही है

यह साबित हो चुका है कि सारी समस्या की जड़ हमारे खेतों में है। यहाँ भारत सरकार का इन खतरनाक रसायनों के प्रति समर्थन जारी है। इन समस्याओं की जानकारी होने और रासायनिक कीटनाशकों के पर्याप्त विकल्प होने के बावजूद सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। कीटनाशक उद्योग को खुशहाल बनाये रखने के लिए नागरिकों की सेहत के साथ खुलेआम समझौता हो रहा है। स्थिति को और बुरा बनाने के लिए सरकार



**India for Safe Food**  
Safe Food - Our Right! No Chemicals, No GM!

जेनेटिकली मोडीफाएड (जी एम) फसलों को प्रोत्साहन देकर समाधान के रूप में उन्हें प्रस्तुत कर रही है। जो खतरनाक और हानिकारक है। इसके परिणाम भी अपरिवर्तनीय हैं।

इसके स्थान पर सरकार को सुरक्षित विकल्पों को समर्थन देना चाहिए। जबकि सरकार तो उनके लिए उचित प्रतिस्पर्धात्मक महल भी उपलब्ध नहीं करा रही। इस समय हमारे अन्नदाता, किसानों के पास कोई विकल्प नहीं है। हकीकत है कि फसल की बढ़ती लागत, कर्ज और कीटनाशकों व अन्य सम्बंधित मामलों की वजह से स्वास्थ्य समस्याएँ बढ़ गयी हैं। इससे किसान गहरे संकट में हैं।

### इसके बावजूद भी खुशखबरी है

खुशखबरी यह है कि दुनिया भर में खेती के सुरक्षित विकल्पों को लेकर प्रयोग हो रहे हैं। उसके फायदे सामने आ रहे हैं। उदाहरण के लिए आंध्रप्रदेश में लाखों किसानों ने गैर-कीटनाशक प्रबंधन (एन पी एम) की खेती को अपनाया। रिपोर्ट बताती है कि किसानों को यह खेती ज्यादा लाभदायक नजर आती है। यदि खाद्य उत्पादन में किसी तरह के कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया गया तो हमारे भोजन में भी कीटनाशक के अंश नहीं मिलेंगे।

भारत सरकार बुराईयों को छोड़ने में हिचकिचाहट दिखा रही है। इतना ही नहीं उसने तो कीटनाशक उद्योग को प्रोत्साहन देने की नीति ही बना ली है। ऐसे में हम उपभोक्ताओं को एक होकर सुरक्षित भोजन की मांग करनी होगी। एक नागरिक होने के नाते सुरक्षित भोजन पाने का हमें पूर्ण अधिकार है।

### आप बन सकते हैं बदलाव के एजेंट-

ऐसे जहर का सेवन करने के लिए हम विवश किये जा चुके हैं। समय आ गया है कि चुनौती की इस घड़ी में एक नागरिक के हैसियत से सरकार से हम माँग करें कि हमारी खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण को उचित तबज्जो, तरजीह दी जाये। सरकार के लिए बड़ी कंपनियों के मुनाफे ही मायने नहीं रखने चाहिए। खतरनाक रसायनों को सरकार खाए तो खाए, हम नागरिकों को ना खिलाये।

### हम सरकार से माँग करते हैं कि :

- जैविक/ पर्यावरणीय/ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा और प्रोत्साहन दें, जिसमें कीटनाशकों और जेनेटिक मोडीफाएड (जैव परिवर्धित) प्रणाली शामिल न हो।
- जैविक भोजन सुनिश्चित करें खाश तौर पर गर्भवती और बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं तथा हमारे नन्हे मुन्नों को।
- उन कीटनाशकों पर प्रतिबन्ध लगाये जाएँ जिन पर अन्य देशों में प्रतिबंध लगा हुआ है।

इस मुद्दे पे ठोस कदम लेने के लिए और अभियान से जुड़े लोगों से संपर्क करने के लिए पन्ने के पीछे दिए गए वेबसाइट को देखें | साथ ही दिए गए नंबर पे missed call दे के अपना सहयोग प्रदान करें |